5

महिला नेतृत्व का सशक्त मिसाल रही है ताई

6

भारतीय सेना की तैयारियाँ देख पाक के होश उड़े

8

तहसीलदार का आरोप- पति कर रही परेशान

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 52 प्रति सोमवार, 5 मई 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल आखिर गिरफ्तार होंगे या नही?

कानूनी दांवपेचों के चलते सदमे में जांच एजेंसियां

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

छत्तीसगढ़ में आईटी, ईडी और सीबीआई की धमक से प्रशासनिक गलियारे से लेकर कई राजनीतिक दलों के दफ्तरों में हलचल तेज देखी जा रही है। एक ओर जहां कांग्रेस अपने नेताओं के बचाव में जुटी है वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार के मामलों को गिन-गिन कर उजागर कर बघेल सरकार के 05 साल के कार्यकाल की यादों को तरोताजा करने में नही चूक रही है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री बघेल गिरफ्तार होंगे या नही? राज्य में भ्रष्टाचार के मसीहा के रूप में बघेल को देखा जाता है। उन्हें उनकी काली करतूतों को लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरते डेढ़ साल बाद भी बघेल कानून की गिरफ्तारी से अछूते बताये जाते हैं। उनके ठिकानों पर सीबीआई समेत अन्य जाँच एजेंसियों दबिश दे चुकी हैं। बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी राजनैतिक गलियारों में यक्ष प्रश्न के रूप में देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के बाद गिरफ्तारी की तलवार का इंतजार लम्बा हो चला है। बताते हैं कि जांच एजेंसियों के पास बघेल की भ्रष्टाचारों की लंबी फेहरिस्त उपलब्ध है। महादेव एप घोटाला हो, शराब घोटाला हो पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की भूमिका भ्रष्टाचार के नायक के रूप में देखी जा रही है।

बघेल एंड कंपनी की बल्ले-बल्ले

सूत्र तस्दीक करते हैं कि बघेल के खिलाफ पुख्ता सबूतों के आधार पर सीबीआई ने छापेमारी तो कि लेकिन उनकी गिरफ्तारी लगातार टलती रही। (शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के हित में लिया बड़ा फैसला, 2621 शिक्षकों के बहाली के फैसले पर लगी मुहर

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ सरकार ने बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2621 शिक्षकों की बहाली पर मुहर लगी। इस ऐतिहासिक निर्णय से नौकरी से निकाले गए शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री साय ने कैबिनेट में ऐतिहासिक निर्णय लिया है, सीधी भर्ती 2023 में सेवा समाप्त 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक

शिक्षकों का सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन किया गया। इसके आलावा प्रदेश सरकार ने कुछ और मुद्दों पर भी बड़े ऐलान लिए है। इससे पहले पिछले सप्ताह छत्तीसगढ़ सरकार पीएससी में परीक्षा या इंटरव्यू में पहुंचने वाले स्टूडेंट्स की फीस नहीं लेगी, जिनसे लिया गया है, उन्हें सरकार वापस करेगी। इसके साथ ही छोटे व्यापारियों का 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25 हजार तक की वैट देनदारियों को माफ किया जाएगा। बीएड शिक्षकों का ये पूरा मामला 2018 में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की ओर से जारी एक गाइडलाइन के बाद सामने आया है। गाइडलाइन में बीएड वालों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के योग्य माना था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर छत्तीसगढ़ के 2897 शिक्षकों पर भी पड़ा। जिस कारण से उनको नौकरी से निकाल दिया गया था।

(शेष पेज 2 पर)

विश्वास ही नहीं होता कि नरेन्द्र भाई हमारे बीच नहीं रहे

स्मृति शेष

-विजया पाठक

अभी हाल में बीजेपी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता नरेंद्र सलूजा का आकस्मिक निधन हो गया। वे वर्षों से मध्यप्रदेश की राजनीति में सक्रियता से कार्य कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में काफी समय काम किया। वे चाहे किसी भी पार्टी में रहे हो मेरा उनसे व्यक्तिगत संपर्क बना रहा। दोनों पार्टियों की प्रेसवार्ता में मेरा मिलना होता था। इसके अलावा भी मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलती रहती थी। वो भी मेरा काफी सम्मान करते थे। उनके निधन से 04 दिन पहले ही बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि दीदी आपके साथ बैठना है बताओ कब आ जाउ। लेकिन क्या पता था कि वो मुलाकात अब कभी नहीं हो पायेगी।

काफी समय तक कांग्रेस में रहने वाले सलूजा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते थे और वे कांग्रेस में प्रदेश मीडिया के समन्वयक रह चुके थे। उस समय सलूजा का भाजपा में चले जाना कांग्रेस के लिए काफी बड़ा झटका था। भाजपा में जाने के बाद सलूजा को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया था। सलूजा अपने शब्द बाणों और चुटीले व्यंग्यों से विपक्ष को करारा जवाब देते थे। चाहे जनहित के मुद्दों को प्रखरता से रखने की बात हो या पार्टी की विचारधारा के प्रसारण की, सलूजा जी अकेले ही सब पर भारी पड़ते थे। सलूजा जी ऊर्जा से भरे जिंदादिल व्यक्तित्व थे। जब वह कांग्रेस में थे तो भाजपा परेशान रहती थी और जब भाजपा में आये तो समूची कांग्रेस उनकी सक्रियता से बहुत प्रभावित थी। वह जहां भी रहे अपना कार्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी और शिद्दत से करते थे। काम करना और बेहतर करने के साथ उन्होंने प्रत्येक संबंध को बखूबी निभाया। उनका असमय जाना पार्टी और हम सभी प्रेस मित्रों के लिए गहरी क्षति है। वे भले हमें छोड़कर अनंत यात्रा पर चले गए हैं किन्तु उनकी स्मृतियां सदैव हमारे साथ हैं। वह सत्ता में रहे हो या विपक्ष में रहे हों उनकी सक्रियता और मुददों पर बेबाक पक्ष रखना सब पर भारी पड़ता था।

प्रवक्ताओं पर रहता है काफी दबाव

नरेन्द्र भाई पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान थे। किन कारणों से परेशान थे। अब वो कारण कभी पता नहीं चल पायेंगे। शायद इसलिए वे मुझसे मिलना भी चाह रहे थे। लेकिन यहां कहना भी जरूरी है कि किसी भी पार्टी के प्रवक्ताओं पर काफी दबाव रहता है। विभिन्न विषयों की जानकारी रखना और उस जानकारी को मीडिया में शेयर करना महत्वपूर्ण कार्य होता है। सवाल जवाब भरी उन्हें हर दिन किसी न किसी न विवाद से ही पड़ता है। इसके साथ ही सत्ता और विपक्ष की छवि को ऐसा प्रदर्शित करना होता है ताकि विश्वसनीयता बनी रहे। नरेन्द्र भाई इस विधा में बहुत पारंगत थे। अपने पक्ष को ऐसे रखते थे कि सामने वाला सवाल नहीं कर पाता था। मैंने इनकी पत्रकारवार्ताओं को बहुत नजदीक से देखा है। हर विषय में इनको सटीक जानकारी होती थी। सरकार और नेताओं की छवि को निखारने का काम प्रवक्ताओं का होता है। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि बावजूद इनको यथोचित स्थान नहीं मिल पाता।

आज भले ही नरेन्द्र भाई हमारे बीच नहीं है लेकिन यादें और उनके साथ बिताये पल हमेशा साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भावपूर्ण श्रद्धांजलि.....

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के हित में लिया बड़ा फैसला, 2621 शिक्षकों के बहाली के फैसले पर लगी मुहर

(पेज 1 से जारी)

3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी

कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार हटाये गए 2621 बीएड सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के राज्य में रिक्त 4,422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला, विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी।

कैसे किया जाएगा समायोजित

इसके साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में एससीईआरटी के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए पदों का सृजन किया जाएगा। समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में उसके पश्चात सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर तत्पश्चात अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा।

आदिवासियों के हित में लिया फैसला

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री साय ने आदिवासी समाज के हित में बड़ा फैसला किया। इसके तहत एसटी-एससी विकास प्राधिकरण और ओबीसी प्राधिकरण का पुनर्गठन करने का फैसला साय सरकार ने बैठक में लिया है। इसके साथ ही बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं पिछड़ी जाति विकास प्राधिकरण को पुनर्गठित किया जाएगा। मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

पांच प्राधिकरों की कमान सीएम के जिम्मे:

इसका उद्देश्य पांचों प्राधिकरणों के कार्य प्रणाली को प्रभावी और सशक्त बनाने के साथ ही उन क्षेत्रों में जनसुविधा के कार्यों को गति प्रदान करना है। इन पांचों प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे होगी। स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और सचिव इन पांचों प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे।

पुनर्गठन और निधि नियम

वर्ष 2004-05 में बस्तर, सरगुजा और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था। इसके बाद साल 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्राधिकरणों के गठन के बाद अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों, मजरा-टोला, पारा-मोहल्लों, वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकताओं के अनेक महत्वपूर्ण काम कराए गए थे। साल 2019 में तत्कालीन सरकार की ओर से इन प्राधिकरणों के कार्य संचालन की प्रक्रिया में अमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया। इस वजह से प्राधिकरणों का न सिर्फ महत्व कम हो गया, बल्कि इनके कार्यों में पारदर्शिता मॉनिटरिंग का अभाव होने के साथ ही शासन स्तर पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रहा। इन स्थितियों को देखते हुए कैबिनेट ने पांचों प्राधिकरणों के पुनर्गठन और निधि नियम के प्रस्ताव को पारित किया।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल आखिर गिरफ्तार होंगे या नही?

(पेज 1 से जारी)

जानकार यह भी बताते हैं कि बघेल को हाजिर होने के लिए सीबीआई और ईडी की ओर से अभी तक कोई समन जारी नही किया गया है। यही हाल बघेल के खिलाफ एसीपी ईओडब्ल्यू में दर्ज प्रकरणों का बताया जाता है। सूत्रों के मुताबिक शराब घोटाले में शामिल कारोबारी और आबकारी अमले के महत्वपूर्ण अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के नाम का परहेज बरतते हुए अपने बयान दर्ज कराये हैं। नतीजतन बघेल को कानूनी दांवपेचों का मिलता फायदा प्रदेश की प्रशासनिक क्षमता पर सवालियां निशान लगाया है। महादेव एप सट्टा घोटाले से बघेल का नाम प्रमुख कड़ी के रूप में सामने आया है।

दुबई में बैठे सटोरी सौरभ चंद्राकर ने बकायदा वीडियो जारी कर दावा किया था कि महादेव एप सट्टा कारोबार को संरक्षण देने के एवज में तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल को लगभग 500 करोड़ रुपये सौंपे गये थे। ईडी के कई आरोपियों ने भी बघेल का नाम दर्ज कराते हुए अपने बयानों में साफ किया है कि शराब घोटाले, महादेव एप घोटाले में भूपेश बघेल भी शामिल थे। बघेल के अलावा पुलिस के दर्जनों अधिकारियों को संरक्षण देने के एवज में हर माह लाखों रुपये जाता था। एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने ईडी को दिये अपने बयानों में स्पष्ट किया है कि सटोरियों के द्वारा तय की गई रकम को हर माह

लगभग आधा दर्जन अफसरों को सौंपा करते थे। बताते हैं कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में घिरे बघेल की गिरफ्तारी को लेकर एजेंसियां पसोपेस में बताई जाती है। केन्द्रीय कर्मचारियों के रुख से भी अब तक स्पष्ट नही हो पाया कि बघेल पर कानूनी शिकंजा कसेगा कि नही। फिलहाल तो बघेल और उनकी टोली कानूनी दांवपेचों से केन्द्र और राज्य सरकार की जांच एजेंसियों से दो चार हो रही हैं। बघेल के दोनों हाथ अभी भी घी में और सिर कढ़ाई में बताया जाता है। यह देखना गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में लपेटे में आये भूपेश बघेल पर कानून का शिकंजा कब कसेगा।

तमाम मामलों में फंसे बघेल का राजनीतिक कैरियर भी दांव पर लगा है। यदि बघेल इन मामलों में फंसते हैं तो निश्चित रूप से उनकी राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जायेगी। बताया जाता है कि आने वाले समय में बघेल के दिन अच्छे नहीं हैं।

बघेल शासन के अधिकतर अधिकारी जेल में

भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में पांच साल शासन किया। इन पांच साल में भूपेश बघेल ने कई भ्रष्टाचार किये। इतना ही नहीं उनके शासनकाल के अधिकतर अधिकारी कानूनी शिकंजे में फंसे हैं। कई तो जेल में हैं या जमानत पर हैं। मतलब साफ है कि बघेल तो भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं बल्कि उनके अधिकारी भी अछूते नही रहे। बघेल की खास सौम्या चौरसिया पर तो कई गंभीर आरोप लगे हैं। और अभी भी जेल में है। इन्होंने पांच साल में ऐसे कारनामें किये कि आज छत्तीसगढ़ बघेल के शासनकाल को भ्रष्टाचार के रूप में देखता है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके ज्यादातर उच्च अधिकारी कानून के शिकंजे में फंसे हैं।

बघेल को लेकर विचार करे आलाकमान

छत्तीसगढ़ में आज भी कांग्रेस प्रमुख पार्टी के रूप में विद्यमान है। अपने अस्तित्व काल से आज तक प्रदेश में सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस ने ही किया है। लेकिन भूपेश बघेल जैसे भ्रष्टाचारी नेताओं के कारण यह राज्य सत्ता से बाहर हो गया है। आज भी समय है कि पार्टी हाईकमान इस राज्य पर गौर करे तो दोबारा सत्ता में वापसी कर सकता है। कांग्रेस पार्टी को बघेल जैसे नेताओं से परहेज करना होगा।

एआई डाटा सेंटर की स्थापना से 500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा: विष्णुदेव साय

■ मुख्यमंत्री ने किया एआई डाटा सेंटर पार्क का शिलान्यास

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-22 में मेसर्स रैक बैंक के एआई डाटा सेंटर पार्क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि एआई डाटा सेंटर की स्थापना से 500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। जब कोई उद्योग लगता है तो रोजगार के कई दूसरे अवसर भी सृजित होते हैं। मेसर्स रैक बैंक द्वारा स्थापित यह एआई डाटा सेंटर 5 मेगावाट क्षमता का है। इस पूरी परियोजना में लगभग एक हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। एआई डाटा सेंटर में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी। इससे एआई पर चलने वाले कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम नवा रायपुर को आईटी मेडिसिटी और फार्मास्युटिकल हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उद्योग नीति के कारण

कम समय में ही देश विदेश से स्थापना हेतु उद्योग आ रहे हैं, यही गति रही तो बहुत जल्द विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का निर्माण हो जाएगा। यह वर्ष छत्तीसगढ़ की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है, हमारी कोशिश रहेगी कि इसी साल स्थापना दिवस पर डाटा सेंटर का लोकार्पण हो जाये। मुख्यमंत्री साय ने एआई डाटा सेंटर की स्थापना करने जा रहे मेसर्स रैक बैंक प्रबंधन के प्रति बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एआई डाटा सेंटर छत्तीसगढ़ के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लेकर आया है। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जय विज्ञान, जय अनुसंधान के मंत्र को साकार करेगा और विकसित छत्तीसगढ़ की बुनियाद बनेगा। देश का ग्रोथ इंजन छत्तीसगढ़ अपने कोयला, स्टील, आयरन ओर, ऊर्जा के लिए पहचाना ही जाता है। अब एआई, सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हमें वैश्विक पहचान मिल रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा छत्तीसगढ़ बना रहे हैं, जहां के युवा सेमीकंडक्टर भी तैयार करेंगे और एआई सेवाएं भी देंगे। एआई डेटा सेंटर से प्रदेश में एआई आधारित सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग और व्यापार जगत के साथ इसका सीधा लाभ लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मिलेगा।

केंद्र सरकार के एआई मिशन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले साल इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी थी। हमें गर्व है कि साल भर के भीतर हमने एआई को लेकर मोदी जी के विजन पर ठोस काम करके दिखाया है। आज कई सारे उद्योग डाटा से संचालित होते हैं। मोबाइल क्रांति के बाद अब एआई का दौर है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र को एआई प्रभावित कर रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की एआई क्रांति देश के लिए मॉडल बनेगी। एआई डाटा सेंटर की स्थापना से एजुकेशन, चिकित्सा, मनोरंजन हो या कारखानों में होने वाला उत्पादन सभी को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सीएसआईडीसी के चेयरमैन राजीव अग्रवाल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, उद्योग सचिव रजत कुमार उपस्थित रहे।

विभागीय मंत्री और डीपीआई के आदेश के बावजूद नरसिंहपुर में नहीं खत्म हो रहे अटैचमेंट

स्कूल शिक्षा मंत्री के अटैचमेंट समाप्ति के निर्देश गृह जिले में ही नहीं हो रहे पालन

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह बार-बार कार्यालय और गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों के संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्देश जारी कर रहे हैं और इस बाबत लोक शिक्षण संचनालय मध्य प्रदेश भोपाल से समय-समय पर अटैचमेंट समाप्ति के लिए आदेश जारी किए गए हैं। अभी हाल ही में एक पखवाड़ा पूर्व मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को अटैचमेंट पूर्णतया समाप्त करने के निर्देश दिए थे और डीपीआई संचालक के के द्विवेदी ने भी मीटिंग लेकर सभी डीईओ से स्पष्ट रूप से कहा कि संलग्नीकरण शीघ्र समाप्त करें।

शिक्षकों को कार्यालय और गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी पर ना लगावे। प्रदेश के एक बड़े मीडिया समूह द्वारा सभी जिलों से जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिए गए नो अटैचमेंट प्रमाण पत्र की पोल खोलते हुए बताया कि उनके पास प्रमाण है कि प्रदेश के कई जिलों में अभी भी सैकड़ो की संख्या में अटैचमेंट जारी है, जिन्हें अतिरिक्त कार्य के नाम पर वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर जिला शिक्षा अधिकारी आदेश जारी करके शिक्षकों को मूल कार्य करने हेतु बाधित करते हैं। इसी तरह जिले के प्रशासनिक अधिकारी समय-समय पर शिक्षकों को राजस्व शाखा में निर्वाचन बीएलओ और जाती प्रमाण पत्र में लगा लेते हैं।

स्वयं विभागीय मंत्री के गृह जिले नरसिंहपुर में मंत्री की मंशा और निर्देशों का किस कदर पालन हो रहा है। यह नरसिंहपुर के शिक्षा विभाग में गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है ना तो जिला शिक्षा अधिकारी और न ही जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मंत्री की आदेशों के परवाह किए जा रहे हैं। वह अपने मनमानी और मन मर्जी भरी कार्य प्रणाली से अटैचमेंट जारी रखे हुए हैं।

मंत्रीजी के कार्यालय में सियाराम पटेल शिक्षक दे रहे दस साल से सेवाएं

नरसिंहपुर में साक्षरता अभियान के नाम और अतिरिक्त कार्य करने के पर लगभग एक सैकड़ा शिक्षक अटैच हैं। जानकार सूत्र बताते हो कि मंत्री जी के कार्यालय को एक शिक्षक सियाराम पटेल अवैधानिक रूप से एक दशक से अधिक समय से देख रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और भारत सरकार से पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार मंत्री और विधायकों के यहां कार्यालय कार्यों के लिए शिक्षकों को रखना पूर्णतया प्रतिबंधित है। फिर भी बगैर आदेश के धड़ल्ले से सियाराम पटेल शिक्षक स्कूल में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए मंत्री के कार्यालय में बैठकर रौब झाड़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं नरसिंहपुर जिले में ही वर्तमान और पूर्व विधायकों के यहां और भी शिक्षक कार्यालय सचिव और निज सचिव के रूप में आदेश और बगैर आदेश के काम करते हुए देखे जा रहे हैं।

"जातिगत जनगणना" को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदेश के सभी जिलों एवं संभागों में प्रेसवार्ताओं का आयोजन

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. भोपाल। कांग्रेस पार्टी द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही "जातिगत जनगणना" की माँग को अंततः भाजपा सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह फैसला कांग्रेस पार्टी के जनहित में किये गए संघर्ष और आवाज का परिणाम है। कांग्रेस पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है और इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानती है। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट भूमिका को जनमानस तक पहुँचाने हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 2 मई से 3 मई 2025 तक सभी जिलों एवं संभागों में प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी द्वारा जातिगत जनगणना की आवश्यकता, इसके लाभ और भाजपा सरकार द्वारा देरी से लिये गये निर्णय पर विचार रखे गये। कांग्रेस पार्टी संकल्पबद्ध है कि जातिगत जनगणना के माध्यम से वंचित वर्गों को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा।

सम्पादकीय

पहलगाम हमले ने पर्यटकों की चहचहाट को खामोशी में बदल दिया

22 अप्रैल 2025 की तारीख पहलगाम की घाटी में गूंजती चीखों और बारूद की गंध के साथ दर्ज हुई। पहलगाम का बैसरन, जहां कई परिवार अपने बच्चों संग छुट्टियां मना रहे थे, कुछ ही पलों में लाशों का मैदान बन गया। हिन्दू हो या नहीं, यह पूछकर हत्याएं की गईं। एक मासूम अपने पिता की लाश से चिपका रोता रहा, एक नवविवाहिता पति को बचाने की गुहार लगाती रही, आतंकियों ने कहा, "जाओ, मोदी को बताना।" ऐसे अनेक हृदयविदारक दृश्यों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। यह हमला एक बार फिर हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। आतंकवादियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर, खतना की पहचान कर निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्या की। यह दृश्य किसी औरंगजेबकालीन दमन का नहीं, बल्कि 2025 के भारत का है। वह भारत जिसका नेतृत्व स्वभाव और संस्कार से हिंदू नीति-निर्माताओं के हाथों में है। यह हमला घृणित मजहबी मानसिकता के चलते किया गया। वह मानसिकता जो काफिरों को जीने लायक नहीं समझती। पहलगाम से जुड़ी सीना भेदती चीखें बताती हैं कि भारत के समक्ष चुनौतियों के जटिल समीकरण हैं और शांति की स्थापना के लिए हर मोर्चे पर ताल ठोककर जवाब देना ही होगा। पहलगाम का सत्य यह है कि यह आतंकी हमला होने पर भी एक वैचारिक युद्ध का चेहरा ही है। ऐसे दुस्साहसपूर्ण हमले यह स्पष्ट करते हैं कि आतंकी केवल बंदूक से नहीं लड़ रहे, वे विचारधारा के अस्त्र से एक संगठित वैश्विक संघर्ष चला रहे हैं, जिसे हम केवल सीमित घटना समझने की भूल कर रहे हैं।

भारत के समक्ष खड़ी यह चुनौती केवल आतंकवाद से नहीं, एक संगठित वैचारिक गठजोड़ से है, जिसमें एक ओर हिंदुत्व को मिटाने का षड्यंत्र है, तो दूसरी ओर राजनीतिक इच्छाशक्ति की परीक्षा। विकसित और तथाकथित 'सभ्य' कहे जाने वाले देशों की अपने हितों तक सीमित रहने की प्रवृत्ति का राजनीतिक विचक के रूप में प्रकट होना और भारत में न्यायपालिका व बौद्धिक तबके द्वारा प्रदर्शित असहज चुप्पी या मतभिन्नता इस वैचारिक चुनौती को और गंभीर बनाती है।

आज हमारे पास यह न मानने का कोई कारण नहीं कि जिहाद केवल आतंक नहीं, बल्कि पूरी मानवता के विरुद्ध एक सभ्यतागत संघर्ष है। पहलगाम का हमला न तो आकस्मिक है, न ही अलग-थलग। यह इस्लामी जिहाद के उस सुनियोजित एजेंडे का हिस्सा है जो हिंदुत्व और भारत की सर्वसांस्कृतिक आत्मा को मिटाने के उद्देश्य से वैश्विक समर्थन और स्थानीय सहानुभूति के सहारे कार्य कर रहा है। इस्लाम के कुछ मध्ययुगीन ग्रंथों और व्याख्याओं में 'काफिर' के प्रति जो दृष्टिकोण मिलता है, वह मित्रता नहीं, घृणा, वहिष्कार और अंततः हत्या तक की स्वीकृति प्रदान करता है। यह केवल मजहबी आग्रह नहीं, राजनीतिक इस्लाम का वह संस्करण है जिसने मजहब को एक सैन्य अभियान में बदल दिया है।

ऐसे अभियानों का समय बेहद सोच समझकर चुना जाता है। फिर उसके अनुसार ही उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। फिर गढ़ा जाता है अल्पसंख्यकवाद का, मुसलमानों पर अत्याचार किए जाने का झूठा विमर्श। अलग-अलग समय पर, अलग-अलग तरीके से इन अभियानों को चलाया जाता है। इसके बाद देश और विदेश में इन कट्टरपंथियों का हमदर्द बनकर बैठी वामपंथी विंडेड सक्रिय हो जाती है। वह अपनी पूरी ताकत झोंक देती है एक झूठा विमर्श खड़ा करने में। उदाहरण के तौर पर, साल 2000 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 21 से 25 मार्च तक भारत दौरे पर थे, तब अनंतनाग जिले के चिट्टीसिंहपोरा गांव में 36 सिख ग्रामीणों का नरसंहार किया गया था। दरअसल, भारत ने पिछले दशक में आधारभूत ढांचे, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। परंतु, यह विकास पथ बार-बार आतंकवाद, कट्टरवाद और तुष्टीकरण की नीतियों से बाधित होता रहा है। इन सबके मूल में है, एक ऐसा गठजोड़, जिसमें स्थानीय वोट बैंक की राजनीति, व्यापक नरमी और बौद्धिक पाखंड शामिल हैं। पहलगाम की घटना बताती है कि अब युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, यह विचारों और संस्कृति की आंतरिक रक्षा की लड़ाई बन चुका है।

सियासी गहमागहमी

जातिगत जनगणना मामले पर प्रदेश अध्यक्ष की तीखी प्रतिक्रिया

भाजपा शासित सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने का फैसला लेने के बाद इसका श्रेय लेने की जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे राहुल गांधी की जीत निरूपित करते हुए कह रही है कि उन्हीं के दबाव के कारण सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। इधर बीजेपी इस बात का जमकर प्रतिकार करते हुए कह रही है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते हुए कभी जाति जनगणना नहीं कराई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने यह बात दोहराई। उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। ऐसा निर्णय केवल मोदी सरकार ही ले सकती है।

अपने बयान पर फंस गये दिग्गी

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा बाबरी मस्जिद को "शहीद" बताने वाले एक पुराने बयान पर सियासी तकरार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां दंगे-फसाद के पीछे कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया है, वहीं दिग्विजय सिंह ने वीडियो के कुछ हिस्सों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। इसमें सिंह ने बाबरी मस्जिद को ढहाने पर उसे "शहीद" कहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि दंगा-फसाद के पीछे कांग्रेस है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दिग्विजय सिंह के एक वीडियो से यह बात प्रमाणित होती है। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह देश मुझे दंगे-फसाद के खिलाफ और समाज में सद्भाव बढ़ाने के लिए जानता है। मैंने कहा था कि उस दौरान 15 दिन तक पीसीसी के दफ्तर में सोया था, हमारा प्रयास था कि दंगा-फसाद न हो। उनकी इस बात को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

भारत बनाने वाले मजदूर और कारीगर असल में अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं।
जब तक उनके हुनर को हक और श्रम को सम्मान नहीं मिलेगा, भारत सही मायने में तरक्की नहीं कर सकता।
आज अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर, मैं उन्हें भारत की प्रगति में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी दिलाने के अपने संकल्प को दोहराता हूं।
-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

आप सभी को "विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस" की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
आज इस अवसर पर मैं देश के कर्म योगी पत्रकार साथियों के साहस ,जज्बे और हौसले को नमन करता हूँ।
-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व का सशक्त उदाहरण रही हैं ताई

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। देश की राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनीतिक दल की अध्यक्ष तक हर पद पर महिलाएं कार्यभार संभाल रही हैं। वर्तमान में कई महिला नेता अपने काम और उपलब्धियों से राजनीति में दमदार भूमिका हैं। इन्हीं महिलाओं में एक नाम सुमित्रा महाजन का है। सुमित्रा महाजन पूर्व लोकसभा स्पीकर रहीं हैं। सुमित्रा महाजन का नगर निगम में पार्षद से लेकर महापौर, मंत्री और फिर लोकसभा अध्यक्ष बनने तक का सफर शानदार रहा। लेकिन क्या आपको पता है कि राजनीति में आने से पहले वह एक रामकथा वाचिका थीं? सुमित्रा महाजन का जन्म 12 अप्रैल 1943 को महाराष्ट्र के चिपलून कस्बे में हुआ था। वह एक कोंकणस्थ ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। सुमित्रा महाजन के पिता का नाम पुरुषोत्तम नीलकंठ साठे और माता का नाम उषा था। उन्होंने एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की है। अपनी पढ़ाई उन्होंने शादी के बाद भी जारी रखी थी। शादी के बाद सुमित्रा महाजन पति के साथ इंदौर शिफ्ट हो गईं। शादी के बाद ही उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान उनका संपर्क रामायण पर प्रवचन करने वाली इंदौर की ही मैना ताई गोखले से हो गई। सुमित्रा उनके साथ रहने लगी। जब मैना ताई बीमार हुईं तो सुमित्रा महाजन ने ही संभाला और प्रवचन देना शुरू किया। बाद में 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' की महिला शाखा राष्ट्र सेविका समिति और महाराष्ट्रीय महिलाओं के संगठन भगिनी मंडल में शामिल हो गईं। यहां से ही उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 1982 में उन्होंने इंदौर नगर निगम चुनाव लड़ा और बहुमत से जीत दर्ज की। साल 1984 में सुमित्रा महाजन को उप-महापौर बनाया गया। एक साल बाद उन्होंने इंदौर से दोबारा चुनाव लड़ा लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुमित्रा ने फिर से राम कथा वाचन करने लगीं। लेकिन साल 1989 में भाजपा ने इंदौर से आम चुनाव के लिए टिकट दिया। तब उन्होंने कांग्रेस नेता प्रकाशचंद्र सेठ को हरा दिया। सुमित्रा महाजन ने एक बार नहीं बल्कि लगातार आठ बार इंदौर क्षेत्र से जीत दर्ज की। साल 2002 में अटल बिहारी सरकार में वह राज्यमंत्री रहीं। बाद में साल 2014 में मोदी सरकार में लोकसभा अध्यक्ष बनीं। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला लिया।

4 मई विश्व हास्य दिवस

हँसी की चिकित्सा से बनाएँ जीवन को रंगीन

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

हर साल मई के पहले रविवार को पूरा विश्व "विश्व हास्य दिवस" मनाता है। यह दिन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हँसी के माध्यम से मानवता को जोड़ने, तनाव मुक्त करने और आंतरिक आनंद को जगाने के लिए समर्पित है। 2025 में यह 4 मई को मनाया जाएगा। हँसी सिर्फ मुस्कान नहीं, बल्कि जीवन का अमृत है। कभी-कभी, यह हंसी सिर्फ एक भावना से कहीं बढ़कर हो जाती है- यह थेरेपी बन जाती है। जब दुख और निराशा हमें घेर लेते हैं, तो एक सच्ची हंसी संजीवनी बूटी का काम करती है, हमें दर्द से उबरने और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तनाव कम करने के लिए तो लाफ्टर थेरेपी एक जानी-मानी तकनीक है।

हँसी थेरेपी: जब हँसना दवा बन जाए

कई बार हँसी थेरेपी का रूप ले लेती है। अस्पतालों में "लाफ्टर क्लब्स" बनाए जाते हैं, जहाँ मरीजों को हँसाकर उनके उपचार में तेजी लाई जाती है। शोध बताते हैं कि 15-20 मिनट की हँसी 2 घंटे की नींद के बराबर आराम देती है। कैंसर, डिप्रेशन और हृदय रोगों में भी हँसी थेरेपी कारगर साबित हुई है।

हँसी: प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार

हँसी न सिर्फ मन को हल्का करती है, बल्कि योग से भी बढ़कर है। इसे "डायाफ्रामिक एक्सरसाइज" कहा जाता है, जो फेफड़ों को मजबूत करती है और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि हँसने वाले लोगों की आयु अधिक होती है, क्योंकि यह रक्तचाप नियंत्रित करके हृदय को स्वस्थ रखती है।

हँसी का इतिहास: एक सकारात्मक क्रांति

1998 में डॉ. मदन कटारिया ने की थी, जो हास्य योग आंदोलन के संस्थापक हैं। आज 70 से अधिक देश इस दिन को उत्साह के साथ मनाते हैं, जो साबित करता है कि हँसी की भाषा सीमाओं से परे है। डॉ. कटारिया ने "फेशियल फीडबैक हाइपोथीसिस" से प्रेरणा लेकर यह सिद्ध किया कि कृत्रिम हँसी भी वास्तविक खुशी ला सकती है। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति जबरदस्ती भी हँसता है, तो उसके मस्तिष्क को लगता है कि वह खुश है और वह एंडोर्फिन (खुशी के हार्मोन) छोड़ता है। इसी विज्ञान पर आधारित पहला विश्व हास्य दिवस मई, 1998 को मुंबई में मनाया गया, और आज यह एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है।

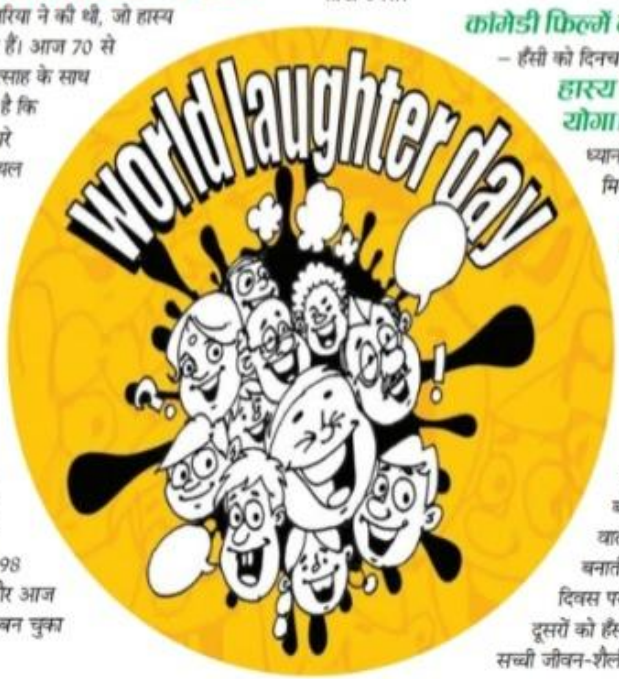

हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए!

चार्ली चैप्लिन ने कहा था, "हँसी के बिना एक दिन, बर्बाद दिन है।" यह बात सच है, क्योंकि हँसी: तनाव कम करती है– कोर्टिसोल (तनाव हार्मोन) घटाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है– श्वेत रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करती है। दर्द निवारक है– एंडोर्फिन रिलीज करके प्राकृतिक पेनकिलर का काम करती है। सामाजिक रिश्ते मजबूत करती है– हँसी साझा करने से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है।

खुलकर हँसने का रहस्य

हम अक्सर बड़े होकर "शिष्टाचार" के चक्कर में हँसना भूल जाते हैं। पर हँसने के लिए कोई मजाक ही क्यों हो? आप:

दर्पण के सामने मुस्कुराएं – यह मस्तिष्क को खुशी का संकेत देता है।

बच्चों के साथ समय बिताएं – वे बिना वजह हँसते हैं, सीखें उनसे।

कॉमेडी फिल्में देखें या जोक्स पढ़ें – हँसी को दिनचर्या का हिस्सा बनाएँ।

हास्य योग (लाफ्टर योगा) आजमाएं – यह ध्यान और हँसी का अनूठा मिश्रण है।

हँसो, जीतो, जीवन को जी भर के जियो!

हँसी मुफ्त की दवा है, जिसे हर कोई ले सकता है। यह न सिर्फ आपको स्वस्थ रखती है, बल्कि आपके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाती है। तो इस विश्व हास्य दिवस पर प्रण लें– "रोज हँसूँगा, दूसरों को हँसाऊँगा, क्योंकि हँसी ही सच्ची जीवन-शैली है!"

किशन भावनानी
एडवोकेट

भारतीय सेना की तैयारियाँ देखकर पाक के होश उड़े

वैश्विक स्तर पर पूरी दुनियाँ देख रही है कि पहले से ही दो जंगों नें पूरी दुनियाँ को डिस्टर्ब कर दिया है और अब तीसरी जंग शुरू होने के मुहाने पर खड़ी है। जैसे उन दोनों जंगों में दुनियाँ बटी हुई नजर आ रही है तो इस होने वाली नई जंग में भी संभवतः कुछ देश बटे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इस तीसरी जंग को ऑपरेशन बदला ? का नाम दिया जा सकता है, अनेक विकसित देशों ने खुलकर समर्थन किया है और यहां तककि चीन नें भी आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की बात कही गई है। सभी पाठक जानते होंगे कि यह जंग भारत-पाकिस्तान की है जो 36 घंटे में शुरू होने हो सकती हैं, जिसका अंदेशा पाक सूचना व प्रसारण मंत्री ने लगाया है। यह युद्ध आतंकवाद के खिलाफ एक रोल मॉडल होगा, जो घर में घुसकर आतंकवादियों के अड्डे नेस्तनाबूत करने का लक्ष्य हो सकता है, जिसकी तैयारी क़रीब-क़रीब पूर्ण हो चुकी है। जो पीएम की सभी मीटिंग्स में तीनों अंगों की सेनाओं के अध्यक्ष, विदेश मंत्री रक्षामंत्री से बैठक हो चुकी है। सेना को फ्रीहैंड का आदेश दिया जा चुका है। बता दें यह सब पहलगाम हमले का जवाब देने की रणनीति के अंतर्गत है, जिसकी अनेक देशों ने निंदा की थी व आतंकवाद के खिलाफ भारत को साथ देने की बात कही थी, चूँकि भारत की धड़ाधड़ रखा तैयारियाँ, मीटिंग्स, एलओसी से डरा पाकिस्तान, बचाव में जुटा, 36 घंटे में हमले या सर्जिकल स्ट्राइक की संभावना है ? तथा भारतीय सेना और रक्षा विभाग की तैयारियों को देखकर पाकिस्तान के होश उड़े, सूचना प्रसारण मंत्री ने भारतीय हमले की 36 घंटे की डेडलाइन निर्धारित की हैं ऐसी जानकारी मीडिया से आ रही है।

बात अगर हम ऑपरेशन बदला की करें तो बहुत ही भयानक कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं! भारत पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सैद्धांतिक तौर पर तैयार हो चुका है। जिस तरह से पीएम ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों और चीफ और डिफेंस स्टाफ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बैठक की है और उन्हें इस मामले में हर तरह की कार्रवाई की खुली छूट दी है, उससे अब यह सिर्फ समय की बात रह गई है कि एक्शन कब शुरू होता है। खासकर राजनीतिक नजरिए से देखें तो आरएसएस के प्रमुख का पीएम से मिलने के लिए उनके आवास पर जाना भी बहुत अप्रत्याशित है। इससे यह भी संदेश मिल रहा है कि जो भी एक्शन होगा, उसका प्रभाव बहुत ही तगड़ा होने जा रहा है और उसी लाइन के मुताबिक रहने वाला है, जिसका संकेत खुद पीएम दे चुके हैं। पहले वाले टारगेट को ध्वस्त करने वाला ऑपरेशन कुछ उसी तरह से करना होगा, जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान में छिपे अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मौत की नींद सुलाने के लिए किया था। भारत इस तरह के टारगेट को साधने के लिए सतह से लेकर नियंत्रण रेखा के काफी अंदर घुसकर पीओके और यहां तक कि पाकिस्तान में भी वार कर सकता है। जहां तक कमांडो ऑपरेशन की बात है तो यह लॉन्च पैड को मिटाने के लिए किए जा सकते हैं। इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे जवान पहले काफी सफल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान या पीओके के ज्यादा भीतर वाले आतंकी ठिकानों या उनके आकाओं को मारने के लिए लंबी-दूरी की मिसाइल से लेकर हवाई हमले तक का विकल्प हो सकता है। लेकिन, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद पाकिस्तान के करीब 80 किलोमीटर अंदर हुई एयरस्ट्राइक के बावजूद कुछ वर्षों में आतंकी संगठनों ने बहुत बड़ी हिमाकत करके दिखाया है। इसलिए, हो सकता है कि हमारी सेना सभी तरह के विकल्पों का इस्तेमाल एक साथ कर दे, ताकि आतंकियों और उनके आकाओं को किसी बिल में छिपने का भी मौका न मिले। क्योंकि, भारत ने जो संकल्प लिया है, उसे दुनिया भर के ज्यादातर देशों का समर्थन हासिल है। पाक को भी मालूम है कि इस बार वह आतंकियों और उनके सरगनाओं को बचा नहीं सकता। इसलिए भारतीय हमले की बात खुद वहां की सरकार के लोग मान रहे हैं। हमला होकर रहेगा और हमें सिर्फ इंतजार इस बात का करना है कि यह कितना भयानक होता है?

बात अगर हम उच्च स्तर पर लगातार चली बैठकों में तथा पाक सूचना प्रसारण मंत्री के 24-36 घंटों में हमले को चार पॉइंट्स में समझने की करें तो, जिस तरह की फोटोज पीएम की मीटिंग की आई है जिसमें सेना और खुफिया विभाग के अफसरों के साथ महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री भी बैठे हैं लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है, दूसरे दिन पीएम राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीपीए और कैबिनेट की सुरक्षा समिति यानी सीसीएस की बैठक भी की, उससे पाक के सूचना मंत्रीने दावाकिया है कि पक्की खुफिया जानकारी है कि अगले 24 से 36 घंटे में भारतीय सेना का अटैक होने वाला है। जो भी हो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पहलगाम के कातिलों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।

(1) पाक लंबे समय से अपनी परमाणु क्षमता को भारत के खिलाफ एक रणनीतिक हथियार के रूप में प्रस्तुत करता रहा है, पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी नेता बार-बार कह रहे हैं कि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ा तो वह परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकते हैं, यह न्यूक्लियर गुब्बारा पाक की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह भारत को सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए परमाणु युद्ध की धमकी देता है, पर भारत ने जिस तरह अपनी सेना को फ्री हैंड दिया है उसका साफ मतलब है कि पाक परमाणु युद्ध की धमकी का भारत पर कोई असर नहीं है, पाक के रक्षा मंत्री ने रॉयटर्स को बताया कि यदि भारत ने सैन्य हस्तक्षेप किया, तो पाक सभी विकल्प खुले रखेगा, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं, लेकिन भारत की सैन्य ताकत, कूटनीतिक रुख, और अतीत की कार्रवाइयों -जैसे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमले-ने पाकिस्तान की इस धमकी को कमजोर किया था, भारत ने इस बार भी स्पष्ट कर दिया है कि वह परमाणु युद्ध की धमकी से डरने वाला नहीं है, और उसकी कार्रवाइयाँ नियंत्रित, लक्षित और प्रभावी होंगी।

(2) पीएम की सेना को फ्री हैंड देने की घोषणा का मतलब है कि अब भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी, यह स्वायत्तता तकनीकी और सामरिक स्तर पर है, जिसमें सेना को यह तय करने की आजादी है कि कब, कहां और कैसे कार्रवाई करनी है, यह नीति पहलगाम हमले के जवाब में आई, जिसे भारत ने पाक आधारित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ा है, फ्री हैंड का अर्थ यह नहीं है कि सेना पाक की तरह अपनी मनमानी करेगी, भारत में लोकप्रिय राजनीतिक नेतृत्व है इसलिए सेना हमेशा उसके मार्गदर्शन में ही काम करती है। फ्री हैंड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सेना को त्वरित और प्रभावी जवाब देने के लिए नौकरशाही से मुक्त करना, भारतीय सेना को फ्री हैंड देने के और भी कई मतलब हैं, जैसे भारतीय सेना पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक या हवाई हमले कर सकती है, भारतीय सेना पाक में स्थित आतंकी बेस कैंपों पर आक्रमण कर सकती है, यह भी हो सकता है कि सेना पाक के कुछ हिस्सों का नेवल ब्लॉकिज भी कर दे।

(3) पाक की चिंताएं और नींद उड़ने के सबूत भारतीय सेना को फ्री हैंड दिए जाने के बाद किस तरह पाक के होश उड़े हुए हैं यह हम उनके रिएक्शन में देख सकते हैं, पाक में इस घोषणा के बाद घबराहट के कई संकेत दिखे हैं, जो यह दर्शाते हैं कि उसका न्यूक्लियर गुब्बारा कमजोर पड़ रहा है। पाक ने तुरंत अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा दिया है। एक्स पर पाक सूचना मंत्री ने दावा किया कि भारत 24-36 घंटे के भीतर हमला कर सकता है। पाक सेना ने एलओसी पर सतर्कता बढ़ाई और 28-29 अप्रैल की रात को कुपवाड़ा बारामूला और अखनूर सेक्टर में गोलीबारी की, जिसका भारत ने जवाब दिया, पाक ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों से हस्तक्षेप की अपील की है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि पाक अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही शांति की वकालत की, यह दोहरा रुख उसकी घबड़ाहट का ही नतीजा है।

(4) उसकी परमाणु धमकी की विश्वसनीयता कई कारणों से कमजोर है, पहली बात पाक परमाणु हमला करके दुनियाँ भर की आर्थिक नाकेबंदी झेलने की स्थिति में नहीं है, पहले से उसकी जनता रोटी के लिए तरस रही है, अगर पाक ऐसी हरकत करता है तो भारत उसको तबाह कर सकता है.पाक के पास 170 परमाणु हथियार हैं, जो भारत के 172 से थोड़े कम हैं, पर भारत के पास परमाणु हथियारों को ढोने और वॉर करने की टेक्नॉलजी पाक से मीलों आगे है, इसका कारण यह है कि भारत की आर्थिक और सैन्य संतुलन, भारत का सैन्य बजट (78.7 बिलियन डॉलर) पाक (7.6 बिलियन डॉलर) से 10 गुना अधिक है पाक आतंकवाद के समर्थन के कारण पहले से ही एफएटीएफ जैसे संगठनों के दबाव में है, भारत की सैन्य कार्रवाई और सबूत उसके अलगाव को बढ़ा सकते हैं।

धरती का बुखार बढ़ता जा रहा है

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

बचपन में हिंदी विषय के अंतर्गत महाकवि कालिदास जी की जीवनी को पढ़ते समय मन में विचार आता था कि क्या कोई इतना मूर्ख व्यक्ति हो सकता है कि जिस शाख पर वह बैठा है और वह उसी को काट रहा हो। मगर आज इस उम्र आते-आते मैं इस प्रश्न का उत्तर हां में पाता हूं। आज के परिदृश्य में एक कालिदास नहीं असंख्य कालिदास नजर आते है, जिनको यह मालूम है कि प्रकृति के साथ छेड़ छाड़ का मतलब विनाश, मगर छद्म विकास की ऐसी धुन की विकास के सामने विनाश नजर नहीं आता। आज मानव उस दोराहे पर खड़ा है कि वो अगर विकास की राह छोड़ प्रकृति की राह पकड़े तो जीवन तो मिलेगा मगर बुखमारी के रूप में मौत निश्चित है और अगर विकास की राह पकड़ कर पेट की भूख शांत करता है तो प्रकृति मानव को उसके कृत्य के लिये दण्डित करने को लालायित नजर आती है। आखिर करे तो क्या करे?

जिस प्रकार अप्रैल के महीने में ही गर्मी अपना प्रकोप दिखाने लगी है उसको देखकर तो रूह कांपने लगी है। मैदानों के साथ साथ पर्वतराज भी तप रहे है। मैं दो हफ्ते पहले हिमाचल प्रदेश के सोलन में था। वहां बढ़े हुए तापमान देखकर अचंभित था। अब निःसंदेह परिवर्तन के लक्षण नजर आने लगे, मगर न समाज को और न ही सरकारों कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आता। जिस प्रकार धरती का बुखार बढ़ रहा है, वह शुभ संकेत नहीं है। जिसका असर कृषि, मानव स्वभाव, पशुपक्षी के व्यवहार पर भी नजर आना प्रारंभ हो चुका है। पशु हिंसक व्यवहार करने लगे हैं, फसलों पर विपरीत प्रभाव नजर आना प्रारंभ हो चुका है जिस वजह से उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गया है, मानव को गर्मी से निजात पाने के लिए अधिक विद्युत की आवश्यकता है जबकि उत्पादन कम होने की वजह से विद्युत की कटौती स्वाभाविक है। तापमान बढ़ा तो स्वाभाविक है कि जल की मांग ज्यादा होगी, मगर अभी से ही जलाशय सूखने प्रारम्भ हो चुके है। बीसवीं सदी के प्रारंभ में जहां 141 सेंटीमीटर वर्षा होती थी वही नब्बे का दशक आते आते 119 सेंटीमीटर रह गई। वहीं भारत में प्रति व्यक्ति पेड़ो की संख्या मात्र 28 ही रह गई है, जबकि एक समृद्ध और स्वस्थ राष्ट्र के लिए 500 से अधिक प्रति व्यक्ति पेड़ो की संख्या होनी चाहिए। इन सब के बावजूद मानव छद्म विकास की रट लगाए हुए है और पेड़ों की बलि निरंतर दी जा रही है। गर्म होता मौसम देखते हुए ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की चेतावनी याद आता है। हॉकिंग ने कहा था कि इंसानों की बढ़ती आबादी और बड़े पैमाने पर ऊर्जा की खपत से पृथ्वी 600 सालों से भी कम समय में आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। हमारी धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है, जिसके कारण मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा है। हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। जंगल मैदान हो गए हैं। नदी, तालाबों, नहरों पर घर बन गए। हवा जहर बना दिया गया।

विगत कुछ वर्षों से, दुनिया के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जलवायु परिवर्तन के इस युग में, 'गर्मी का प्रचंड बढ़ना' केवल एक वाक्यांश नहीं, बल्कि एक चिंताजनक वास्तविकता बन गया है। वैज्ञानिकों ने कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि धरती का पारा बढ़ रहा है और इसमें हर साल इजाफा हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह परिवर्तन मुख्य रूप से मानवजनित कारणों के कारण हो रहा है, जिसमें औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, और जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग प्रमुख हैं। जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में, वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान पिछली सदी के दौरान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इस तापमान वृद्धि का सबसे बड़ा कारण ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। ये गैसें वायुमंडल में सूर्य की ऊर्जा को फंसाकर पृथ्वी को गर्म करती हैं, जिसे 'ग्रीनहाउस प्रभाव' कहा जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर इसी तरह ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, तो भविष्य में गर्मी और भी अधिक प्रचंड हो सकती है। इस संकट से निपटने के लिए, वैश्विक समुदाय को संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। पेरिस समझौते जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौते एक सकारात्मक कदम हैं, लेकिन इन प्रयासों को और भी व्यापक और तेजी से लागू करने की आवश्यकता है। सतत विकास और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ना, वनों की कटाई को रोकना, और जीवाश्म ईंधनों के विकल्पों को अपनाना इस संकट से निपटने के कुछ उपाय हैं।

आज आवश्यकता है कि मानव-समाज अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। मानव-समाज के छोटे छोटे प्रयास भी प्रकृति को जीवन दे सकती है। वैसे सरकारें समाज का आईना होती है, समाज जो चाहता है उसी प्रकार लुटियंस की दिल्ली अपना व्यवहार, आचरण और भाषा का निर्माण करती है। अगर आज सरकार विकास का सपना दिखलाती है तो इसका मतलब समाज वो चाहता है। मगर समाज और सरकारों का दायित्व यह भी बनता है कि जीवन प्रदान करने वाली प्रकृति का भी सम्मान करे। हम सिर्फ व्यवस्थाओं को दोषी मानते हुए हाथ पर हाथ रख कर भी नहीं बैठ सकते, आज हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर प्रकृति के लिए कार्य करना होगा। जिस प्रकार मनुष्य बुखार हो जाने के उपरांत पानी की पट्टी का इस्तेमाल करता है। उसी प्रकार मानवनिर्मित विकास रूपी रेड-हीट को कम कर पेड़ो वाली ग्रीन-हीट को स्थापित करना होगा वही ग्रीन-हीट बदल रूपी ब्लू-हीट को अपनी ओर आसित कर वर्षा करा सकती है और तब ही धरती का बुखार कम होगा, तब ही मानव सभ्यता बच पाएगी।

शब्द हिंसा का बेलगाम समय!

जरूरी है मीडिया का भारतीयकरण

प्रो. संजय द्विवेदी
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के जनसंचार विभाग में आचार्य और अध्यक्ष

यह 'शब्द हिंसा' का समय है। बहुत आक्रमक, बहुत बेलगाम। ऐसा लगता है कि टीवी न्यूज मीडिया ने यह मान लिया है कि शब्द हिंसा में ही उसकी मुक्ति है। चीखते-चिल्लाते और दलों के प्रवक्ताओं को मुर्गों की तरह लड़ाते हमारे एंकर सब कुछ स्क्रीन पर ही तय कर लेना चाहते हैं। यहां संवाद नहीं है, बातचीत भी नहीं है। विवाद और वितंडावाद है। यह किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का संवाद नहीं है, आक्रामकता का वीभत्स प्रदर्शन है। निजी जीवन में बेहद आत्मीय राजनेता, एक ही कार में साथ बैठकर चैनल के दफ्तर आए प्रवक्तागण स्क्रीन पर जो दृश्य रचते हैं, उससे लगता है कि हमारा सार्वजनिक जीवन कितनी कड़वाहटों और नफरतों से भरा है। किंतु स्क्रीन के पहले और बाद का सच अलग है। बावजूद इसके हिंदुस्तान का आम आदमी इस स्क्रीन के नाटक को ही सच मान लेता है। लड़ता-झगड़ता हिंदुस्तान हमारा 'सच' बन जाता है। मीडिया के इस जाल को तोड़ने की भी कोशिशें नदारद हैं। वस्तुनिष्ठता से किनारा करती मीडिया बहुत खौफनाक हो जाती है।

सूचना और खबर के अंतर को समझिए

हमें सोचना होगा कि आखिर हमारी मीडिया प्रेरणाएं क्या हैं? हम कहां से शक्ति और ऊर्जा पा रहे हैं। हमारा संचार क्षेत्र किन मानकों पर खड़ा है। पश्चिमी मीडिया के मानकों के आधार पर खड़ी हमारी मीडिया के लिए नकारात्मकता, संघर्ष और विवाद के बिंदु खास हो जाते हैं। जबकि संवाद और संचार की परंपरा में संवाद से संकटों के हल खोजने का प्रयत्न होता है। हमारी परंपरा में सही प्रश्न करना भी एक पद्धति है। सवालों की मनाही नहीं, सवालों से ही बड़ी से बड़ी समस्या का हल खोजना है, चाहे वह समस्या मन, जीवन या समाज किसी की भी हो। इस तरह प्रश्न हमें सामान्य सूचना से ज्ञान तक की यात्रा कराते रहे हैं। आज 'सूचना' और 'ज्ञान' को पर्याय बनाने के जतन हो रहे हैं। सच यह है कि 'सूचना' तो समाचार, खबर या न्यूज का भी पर्याय नहीं है। सूचना कोई भी दे सकता है। वह कहीं से भी आ सकती है। सोशल मीडिया आजकल सूचनाओं से ही भरा हुआ है। किंतु ध्यान रखें खबर, समाचार और न्यूज के साथ जिम्मेदारी जुड़ी है। संपादकीय प्रक्रिया से गुजरकर ही कोई सूचना, समाचार बनती है। इसलिए संपादक और संवाददाता जैसी संस्थाएं साधारण नहीं है।

हर व्यक्ति नहीं हो सकता पत्रकार

यह कहना आजकल बहुत फैशन में है कि इस दौर में हर व्यक्ति पत्रकार है। हर व्यक्ति फोटोग्राफर है। हर व्यक्ति कम्युनिकेटर, सूचनादाता, मुखबिर हो सकता है, वह पत्रकार कैसे हो जाएगा? मेरे पास कैमरा है, मैं फोटोग्राफर कैसे हो जाऊंगा। विशेष दक्षता और प्रशिक्षण से जुड़ी विधाओं को हल्का बनाने के हमारे प्रयासों ने ही हमारी मीडिया या संवाद की दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यह वैसा ही है जैसे कपड़े प्रेस करने वाले या प्रिंटिंग प्रेस वाले अपनी गाड़ियों पर 'प्रेस' का स्टिकर लगाकर घूमने लगे। मीडिया में प्रशिक्षण प्राप्त और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बिना आ रही भीड़ ने अराजकता का वातावरण खड़ा कर दिया है। लोकमान्य तिलक,महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, बाबासाहेब आंबेडकर, पं.जवाहरलाल नेहरू, मदनमोहन मालवीय, माधवराव सप्रे जैसे उच्च शिक्षित लोगों द्वारा प्रारंभ और समाज के प्रति समर्पित पत्रकारिता वर्तमान में कहां खड़ी है। भारत सरकार के आग्रह पर प्रेस कौंसिल आफ इंडिया ने पत्रकारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के निर्धारण के लिए एक समिति भी बनाई थी, जिसके समक्ष मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर मिला था। बाद में उस कवायद का क्या हुआ पता नहीं।

समाज की रूचि का करें परिष्कार

समाज की रुचि का परिष्कार और रूचि निर्माण भी मीडिया की जिम्मेदारी है। अपने पाठकों, दर्शकों को समय के ज्वलंत मुद्दों पर अपडेट रखना, उनकी बौद्धिक, नागरिक चेतना को जागृत रखना भी मीडिया का काम है। जबकि देखा यह जा रहा है कि पाठकों की पसंद के नाम पर कंटेंट में गिरावट लाने की स्पर्धा है। ऐसे कठिन समय में मीडिया के दायित्वबोध और सरोकारों पर बातचीत बहुत जरूरी है। प्रिंट मीडिया ने भी साहित्य, कलाओं, प्रदर्शन कलाओं और मनुष्य बनाने वाली सभी विधाओं को अखबारों से निर्वासन दे दिया है। मीडिया सिर्फ दर्शक बना रहे यह भी ठीक नहीं। उसे राष्ट्रीय भावना और जनपक्ष के साथ खड़े रहना चाहिए।

देखा जाए तो समाज में फैली अशांति, स्पर्धा, लालसाओं और संघर्ष के बीच विचार के लिए सकारात्मक मुद्दे उठाने ही होंगे। मीडिया खुद अशांत है और गहरी स्पर्धा के कारण सही-गलत में चुनाव नहीं कर पा रहा है। ऐसे में मीडियाकर्मियों की जिम्मेदारी है कि खुद भी शांत हों और संवाद की शुचिता पर काम करें। वसीम बरेलवी लिखते हैं-

कौन सी बात कहां, कैसे कही जाती है।
वो सलीक़ा हो तो हर बात सुनी जाती है।

तहसीलदार ने पत्नि और एसपी कटनी पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप

▪ तहसीलदार का आरोप, एसपी कटनी के कहने पर पत्नि कर रही परेशान

-संवाददाता

जगत प्रवाह. दमोह। अपनी पत्नी को बचाने के लिए दमोह के तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तक गुहार लगा रहे हैं। तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा की पत्नी ख्याति मिश्रा उप पुलिस अधीक्षक कटनी में पदस्थ हैं। शैलेंद्र बिहारी का आरोप है कि उनकी पत्नी को पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत रंजन गुमराह कर रहे हैं। अभिजीत रंजन के कहने पर मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ झुठे आरोप लगाए हैं। जबकि सत्यता है यह है कि मेरी पत्नी अभिजीत रंजन के कहने पर एवं उनके अनुसार ही चल रही है। जैसा अभिजीत रंजन बोलते हैं वैसा ही मेरी पत्नी उनकी बात मानती है। मुझे हर प्रकार से मेरी पत्नी और पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत रंजन प्रताड़ित कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं डीजीपी को भी लिखित शिकायत की है कि मुझे अभिजीत रंजन से अपनी जान का खतरा है। अभिजीत रंजन मेरी पत्नी को मुझसे अलग करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं और मुझे झुठे आरोप-प्रत्यारोप में फंसा रहे हैं। अभी पूर्व में मुझे दमोह से उनके अधीनस्थ अंकित मिश्रा, प्रभारी बस स्टैंड कटनी द्वारा उठा लिया गया। यह कहकर कि आपको पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत रंजन ने मुलाकात के लिए बुलाया है और मुझे कटनी बुलाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया एवं रात भर बंद करके मुझे प्रताड़ित किया गया। अभिजीत रंजन भी वहां मौजूद थे तथा उनके द्वारा दबाव डाला गया कि तुम ख्याति से तलाक ले लो और नहीं तो तुम्हे जान से मार देंगे। जब मैंने मना कर दिया और कहा कि मेरे साथ यह क्यों कर रहे हो तो आनन-फानन में अभिजीत रंजन ने अपने अधीनस्थ चौकी प्रभारी बस स्टैंड अंकित मिश्रा की सरकारी रिवाल्वर निकाल कर मेरे सर पर तान दी। मैंने उनसे गुहार लगाई और कहा कि ठीक है जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं और वहां से अपनी जान बचाकर रात के 3:00 बजे कटनी से भोपाल के लिए भाग गया। शैलेंद्र बिहारी शर्मा का कहना है कि अभिजीत रंजन ने अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों को मेरे पीछे और मेरे परिवार के पीछे लगा रखा है। मुझे पुलिस अधीक्षक से जान का खतरा है। मैंने कई बार अपनी पत्नी को रंगे हाथों शहर के जंगल में बना एक रिसॉर्ट शहदार में पूर्व में उनको पकडा था। जब मैं उनको पकड़ तो वहां से मेरी पत्नी ख्याति मिश्रा और अभिजीत रंजन मुझे देखकर भाग निकले। ऐसे कई बार मेरी पत्नी कटनी के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में अभिजीत रंजन के साथ पाई गई। जब-जब मैं कटनी के सरकारी निवास में जाता था तो मुझे घर में घुसने नहीं दिया जाता था। ना ही मेरे बच्चे को मुझसे मिलाया जाता था। मेरी पत्नी द्वारा मुझ पर झुठे आरोप लगाए गए हैं। मुझे मेरी पत्नी और पुलिस अधीक्षक से जान का खतरा है। कभी भी मुझे मरवा सकते हैं। मैं विगत कई महीनों से अपनी पदस्थ जगह दमोह में नहीं जा पा रहा हूं। वहां पर भी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मेरे सरकारी निवास दमोह में मेरी खुफिया जानकारी निकालना, मेरे बारे में पता करने के लिए लगा रखा है। मेरी पत्नी एवं पुलिस अधीक्षक के संबंध की जानकारी पूरे मध्यप्रदेश एवं पूरे कटनी जिले एवं पूरे पुलिस मुख्यालय को है एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को

कृषि उपज मंडी की अव्यवस्थाओं से किसान परेशान शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा सुधार

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी कला। इन दिनों देवरी कृषि उपज मंडी में चारों ओर अव्यवस्थाओं का अंबाला लगा हुआ है। जिसके चलते कृषि उपज मंडी परिसर में आने वाले किसानों और व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कारण किसानों का मंडी से मोहभंग हो रहा है। यह के व्यापारी और किसान समस्याओं से जूझने को मजबूर हैं। विभिन्न स्तरों पर मंडी की अव्यवस्थाओं की शिकायत की गई फिर भी व्यवस्थाएं सुधारने का नाम नहीं ले रही है। कृषि उपज मंडी परिसर में आवारा पशुओं का आतंक है। सब्जी के किसान और व्यापारी आवारा पशुओं को लेकर परेशान हैं। क्योंकि जैसे ही माल खुले में रखा जाता है, गाय-बैल जैसे आवारा पशु इन पर टूट पड़ते हैं। जिसके कारण किसान और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मंडी परिषद की नालियों में गंदगी का आलम है। व्यापारियों का आरोप है कि मंडी शुल्क के नाम पर मंडी प्रशासन शुल्क की वसूली तो पूरी करता है, लेकिन व्यवस्थाएँ नहीं देता। ग्राम घोषिपट्टी निवासी किसान उमाशंकर लोधी ने मंडी परिषद में व्याप्त अव्यवस्थाओं के संबंध में मुख्यमंत्री शिकायत निवारण 181 में भी शिकायत दर्ज की है। फिर भी व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही है। 181 पर शिकायत दर्ज करते हुए किसान ने बताया कि मंडी परिसर में साफ सफाई नही हो रही है। और मंडी परिषद में बने शौचालय काफी समय से बंद पड़े हुए हैं। जिस के कारण किसानों को प्रसाधन के लिए परेशान होना पड़ है। और ना पीने के पानी की व्यवस्था है। आवारा जानवर मंडी परिषद में खुले घूमते रहते हैं। जिसके चलते मंडी परिषद में अवस्थाएं बनी हुई है। और देवरी कृषि उपज मंडी में आने वाले किसान और व्यापारी दोनों परेशान है। इसके बावजूद भी मंडी प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे है।

महिला बाल विकास शहरी द्वारा नगर पालिका सभाकक्ष में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। महिला बाल विकास शहरी द्वारा नगर पालिका सभाकक्ष में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती अर्चना पुरोहित, महिला बाल विकास समिति अध्यक्ष श्रीमती रिचा तिवारी, भाजपा जनप्रतिनिधि सदस्य एवं मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा तिवारी एवं सभी लाड़ली लक्ष्मी बालिकाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन महिला बाल विकास पर्यवेक्षक श्रीमती श्वेता पटवा मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रचलन कन्या पूजन के साथ प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली लाडली लक्ष्मी बच्चियों को सम्मानित किया गया। लाड़ली लक्ष्मी बालिका को प्रशस्ति पत्र भेंट दिए गए। कुछ बच्चियों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी के अनुभव सभी के समक्ष साझा किए गए। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी श्रीमती प्रीति यादव , पर्यवेक्षक श्रीमती श्वेता पटवा मिश्रा, पर्यवेक्षक श्रीमती लता नागराज, ब्लॉक कार्डिनेटर श्रीमती कीर्ति उपाध्याय एवं कार्यकर्ताएं उपस्थित रही। कार्यक्रम का आभार परियोजना अधिकारी श्रीमती प्रीति यादव द्वारा प्रकट कर कार्यक्रम का समापन किया।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जैयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)